*182. *[The Questioners (Shri Triloki Nath Chaturvedi and Dr. Murli Manohar Joshi) were absent. For answer vide Col......infra.]*

*183. *[The Questiouer (Shri V. Narayanasamy) was absent. For answer vide Col...infra.]*

*184. *[The Questioner (Shri Satish Pradhan) was absent. For answer vide Col....infra.]*

*185. *[The Questioners (Shri Tulasidas Majji and Dr. Shrikant Ramchandra Jichkar) were absent. For answer vide Col....infra.]*

सिंचाई की अपर्याप्त सुविधायें

†186. **श्री आस मोहम्मद :**
श्री ईश दत्त यादव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने **की कृपा करेंगे कि :**

(क) **क्या** यह सच है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के 46 वर्षों के पश्चात् भी देश में सिंचाई की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने सिंचाई की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए क्या-क्या प्रयास किए हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (c) Irrigation potential has increased from 22.6 million hectares during the pre-plan period to about 85.05 million hectares at the end of 1993-94 and is likely to increase to 96.89 million hectares at the end of 8th Five Year Plan. The progress in creation of irrigation facilities is considered satisfactory keeping in view the availability of funds. For full utilisaion of the created facilities, a Centrally Sponsored Command Area Development Prgramme has been in implementation since 1974-75. At present, it covers a Culturable Command Area (CCA) of 21.18 million hectares in 181 irrigation projects spread over 22 States and 2 UTs. A National Water Management Project is also under implementation in 98 projects covering a CCA of about 3.28 million hectares for improving the efficiency of the existing irrigation facilities.

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर सभापति जी, मेरा प्रश्न पूछने का जो मन्तव्य था उसका समुचित और सही उत्तर सरकार की ओर से नहीं दिया गया। यह बात सही है कि मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें इन्होंने कहा है कि पूर्व अवधि में सृजित 22.6 मिलियन हैक्टयर से बढ़ कर 85.05 मिलियन हैक्टयर सिंचाई क्षमता हो गई है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 96.89 मिलियन हैक्टयर हो जाएगी। मान्यवर, मैं इस उत्तर को सही तो मानता हूं लेकिन संतोष-जनक नहीं मानता, क्योंकि 46 वर्षों में इस देश में सिंचाई की जो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए थी वह सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी और आज भी देश में 60 प्रतिशत से अधिक भूमि असिंचित पड़ी हुई है।

MR. CHAIRMAN: Please ask your quesion.

श्री ईश दत्त यादव : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। जिसका देश के कृषि उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इसमें भी मैं संदेह नहीं कर रहा हूं कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने प्रयास किए हैं, लेकिन जो प्रयास होने चाहिए थे वे भरपूर प्रयास नहीं किए गए। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रश्न ही पूछ रहा हूं माननीय मंत्री जी से कि क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस देश में कितने प्रतिशत भूमि अब तक सिंचित हो सकी है और कितने प्रतिशत भूमि जो कृषि योग्य है आज भी असिंचित पड़ी हुई है और उसको सिंचित नहीं किया जा सका है ?

† सभा में यह प्रश्न श्री ईश दत्त यादव द्वारा पूछा गया।

SHRI P. K. THUNGON: Sir, the geographical area is 328.75 million hectares. The reporting area is 385.02 million hectares. Net area sown is 142.24 million hectares. Net irrigated are is 47.43 million hectares. Gross irrigated area is 61.78 million hectares. The total cropped area is 185.46 million hectares. This is the total picture for the whole country.

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। इस क्षेत्र में जो क्षमता बढ़ी है, उसके बारे में तो पहले ही उत्तर दे दिया है। हम तो स्पष्ट और स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं इस देश की कितनी प्रतिशत भूमि अब तक सिंचित हो सकी है और कितनी असिंचित पड़ी है जिसके लिए कि आपको कोशिश करनी है ? इसका उत्तर आप नहीं दे रहे हैं।

SHRI P. K. THUNGON: Sir, probably, the hon. Member was not very much attentive. I have stated that the net irrigated area is 47.43 million hectares.

AN HON. MEMBER: He wants to know the percentage.

SHRI ISH DUTT YADAV: What is the unirrigated area?

SHRI P. K. THUNGON: Percentage can be worked out. I have not worked it out.

MR. CHAIRMAN: Do some mathematical exercise at home.

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर, दूसरा सप्लीमेंटरी छोटा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था इन्होंने अपने उत्तर में कहा है और वह भी खूबसूरती से कहा है कि जितनी हमको निधियां उपलब्ध हैं या जितना फंड अलाट है, उससे हम सिंचाई संतोषजनक मानते हैं। मैं मंत्रीजी से जानना चाहता था कि क्या आप सिंचाई के विस्तार के लिए और भी फंड की आवश्यकता समझ रहे हैं जो क्षेत्र जिसकी जानकारी आपको नहीं, मैं उसको प्रैस नहीं कर रहा आज भी देश में असिंचित पड़ा हुआ है, क्या उसके लिए आप नए फंड की रिक्वैस्ट कर रहे हैं और क्या नई परियोजनायें चालू करने के लिए सरकार के विचाराधीन हैं ? कोई प्रकरण है इस प्रकार का ?

SHRI P. K. THUNGON: Sir, there are a number of on-going projects and also new projects. Those will take care of the further irrigation needs. But, so far as the need to increase the finances is concerned, it is there. But I would request the hon. Member to use his influence also to impress upon the Finance Ministry and the Planning Commission to allot more funds.

SHRI ISH DUTT YADAV: That is beyond my power.

यह तो आपने आन-गोईंग योजनाओं या प्रोजक्ट्स के बारे में बताया है। हम नई योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसी योजनाएं आपके डिपार्टमेंट में विचाराधीन हैं ?

SHRI P. K. THUNGON: Sir, I have said that there are a member of such schemes. The list is very long. So, I can supply it to the hon. Member.

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति जी, अभी सरकार की तरफ से जो जवाब आया है, मैं कृषि मंत्रालय और सिंचाई विभाग दोनों की मजबूरियों को समझ रहा हूं और यह भी समझ रहा हूं कि जब तक वित्त मंत्रालय इनको पैसा नहीं देगा तब तक यह देश की जमीन की सिंचाई का इंतजाम नहीं करेंगे और लोग आसमान की तरफ देखते रहेंगे और जब पानी बरसेगा तो फसल होगी और पानी नहीं बरसेगा तो अकाल होगा, दुर्भिक्ष होगा और बेवक्त मौत होगी, लेकिन मैं सरकार से साफ-साफ यह जानना चाहता हूं जिसकी तरफ कि मूल-प्रश्नकर्त्ता ने भी इशारा किया है कि कितनी पंचवर्षीय योजनायें और लगेंगी कि हिन्दुस्तान की खेती लायक जमीन की सिंचाई हो सके ? इस बात का

आश्वासन इस सदन, इस सदन के माध्यम से राष्ट्र और राष्ट्र के किसानों को यह सरकार कभी दे पाने की हालत में होगी कि नहीं ? आठ पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई की जो उपलब्धि हुई है, वह मुश्किल से 40 सकड़ा जमीन की हो रही है तो अभी कितनी पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई की यह रफ्तार रेंगते हुए संपूर्ण खेती की सिंचाई के लिए संभव हो पाएगी, यह हम साफ-साफ जानना चाहेंगे ?

SHRI P. K. THUNGON: Sir, for the information of the hon. Member, I would like to say that in the First Plan, Rs. 376.24 crores were allocated for our major and medium irrigation projects. Sir, in he Seventh Five-Year Plan,....

MR. CHAIRMAN: He is asking as to how many Five-Year Plans it would take, if you can look into the future.

श्री जनार्दन मिश्र : सर, हम पूछ रहे है कि अब तक खेती को जितना सींचा गया है इतनी पंचवर्षीय योजना के चलते, उस रफ्तार से कितनी पंचवर्षीय योजना और लगेगी ताकि सारे देश की खेती की सिंचाई का इंतजाम हो सके ?

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: He is gradually coming to that.

SHRI P. K. THUNGON: I am coming to that, Sir. In the Seventh Five-Year Plan it was raised to Rs. 11,101.29 crores. The outlay for 1994-95 is Rs. 4,285.25 crores. The target for the Eighth Five-Year Plan is Rs. 22,414.53 crores. The Plan period is five years. We do not have a ten-year or a twenty-year plan at the moment. Therefore, it is very difficult to say as to after how many Five-Year Plans, full irrigation would be achieved. It is very difficult to say at this stage.

श्री जनार्दन मिश्र : बाद में जवाब दे दीजिए इसका। सभापति जी, मैं आपसे अपनी रक्षा की गुहार चाहूंगा। मैं अपनी रक्षा नहीं चाहता हूं, देश के किसानों की रक्षा चाहता हूं, जिनकी जमीन अभी असिंचित है। इतने दिन स्वतंत्रता को मिले हो गये, यह एक प्रश्न-चिह्न सरकार चलाने वालों पर है, इन्हीं लोगों पर ही नहीं, हम भी कुर्सी पर रहे होंगे तो हम पर भी लगा है। हमें ईमानदारी से इस बात को महसूस करना चाहिए कि कितने दिन और, वह किसान जिसके खेत को पानी नहीं मिलता, वह आसमान की तरफ देखता रहेगा ? इसका जवाब जब भी सरकार दे सकती हो, आज दे सकती हो आज दे या दस दिन बाद दे या जो कोई सरकार आए उसको देना ही पड़ेगा। इसलिए मैं जानता चाहता हूं कि कितने दिन और लगेंगे ? मंत्री जी कहते हैं कि कहना मुश्किल है। इससे काम नहीं चलेगा। इससे तो गांव के किसान को खेती की सिंचाई का इंतजाम नहीं हुआ, यह संदेश जाएगा इनके जवाब से। इसलिए सरकार को साफ-साफ बताना पड़ेगा कि कितने दिनों में उसके खेत की सिंचाई का इंतजाम हो जाएगा ? इसका सही जवाब आना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Mr. Misra, to answer your question, to my mind, the Planning Commission, the Finance Ministry and the Ministry of Water Resources have all to come together to give this prospect as to how many Five-Year Plans it would take. There are many factors involved. There is the question of administration. It has to be seen whether the States would carry it out. Innumerable factors are involved. Therefore, you cannot expect the Minister to say as to how many Five-Year Plans would be required.

SHRI JANESHWAR MISRA: Sir, I understand it, but he should say something.

वह मजबूरी तो मैं महसूस कर रहा हूं, साहब।

MR. CHAIRMAN: We can only hope that too many Five-Year Plans would not be required for solving this problem.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Mr. Chairman, Sir, I would like to point out to the hon. Minister, through you, that during the last several years, the

Krishna Delta, with about 12 lakh acres, is not receiving the required water from the Nagarjunasagar Project, particularly, during the drought years. Sir, there are several small rivers between Nagarjunasagar and the Krishna Delta, but they are just flowing into the sea. In this connection, there has been a proposal and the people have been repeatedly requesting the Government to modernise the Krishna Delta and also to take up the Pulichintla Reservoir Project so that the Krishna Delta would have adequate water and the *ayacut* would be stabilised. I would, therefore, like to know whether there is any proposal from the Andhra Pradesh Government to take up the modernisation of the Krishna Delta and also the Pulichintla Project between Nagarjunasagar and the Krishna Barrage.

SHRI P. K. THUNGON: Sir, I do not have the exact particulars now. I can supply that. But in general, the proposals come from the State Governments and they are examined here. After examination, if something is found lacking, they are sent back to the State Governments. In the process, it takes a little bit more time. But we would certainly keep this in mind. I quite understand the concern of the hon. Member for according priority, importance, to this project.

श्री जगन्नाथ मिश्र : सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उनकी जानकारी है कि केन्द्रीय सिंचाई मंत्री ने कुछ वर्ष पहले राज्यों के सिंचाई मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और उस बैठक के निर्णय के अनुसार राज्यों के मंत्रियों की एक उपसमिति बनाई गई थी? जो सिंचाई क्षमता सृजित हुई है सारे देश में उस क्षमता का उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा, क्या कारण हैं, उन कारणों का उल्लेख करते हुए समिति ने अनुशंसा की थी कि एक खाई है क्षमता सृजन में और उपयोगिता में? और, उसकी वजह यह है कि भारत सरकार से या राज्य सरकारों से जो धनराशि सिंचाई योजनाओं में लगाई ती है, उसके अंतर्गत सिंचाई किसानों की जमीन तक पहुंचे मुख्य नहर से, उसका व्यय कौन करेगा? सिंचाई योजनाओं में वह व्यय सम्मिलित नहीं होने की वजह से लाभान्वितों पर जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि पंचायत के स्तर से, प्रखंड स्तर से वह फील्ड चेनल्स बनायें और फिर सिंचाई क्षमता का उपयोग करें। भारत सरकार से अनुशंसा की गई राज्य मंत्रियों की ओर से कि यह व्यय भी इस सिंचाई योजना का भाग बने, तभी सिंचाई क्षमता जो हम सृजित करते हैं, उसका सही उपयोग कर सकते हैं। क्या मंत्रियों ने जानकारियां दी कि सिंचाई क्षमता जो सृजित हुई है, उसकी उपयोगिता क्या है? उपयोगिता नहीं होने के कारण क्या है? उन कारणों का जब उल्लेख राज्य मंत्रियों ने किया था, क्या उस पर भारत सरकार ने ध्यान दिया, कार्रवाई की? अगर कार्रवाई की तो वह कार्रवाई क्या है?

SHRI P. K. THUNGON: Sir, it is right that when the irrigation potential is created as per the project reports, whatever amount of area is shown, sometimes it is not achieved. There is always some lag found in many places. Therefore, the steps taken are as follows:—

-- implementation of the CAD projects continues since 1974-75;

— adaptive trials are being carried out;

— demonstration and training to farmers are being carried out;

— farmers' participation in irrigation is sought;

— introduction of multiple cropping pattern is taken care of;

—re-appraisal of actual potential of old scheme;

-- uniform data reporting;

— annual performance review;

— introduction of CAD approach to minor irrigation schemes etc.

डा० जगन्नाथ मिश्र : हम जानना चाहते थे कि निश्चित रूप से राज्यों की उपयोगिता की जो खाई बनी है क्षमता के विरुद्ध, उसको कैसे पाटा जाए, उसके लिए जो संस्थायें थीं, भारत सरकार ने उन संस्थाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कार्रवाई की है तो कहां की, कैसे की? क्योंकि अभी उन्होंने सूचना दी कि इतने मीलियन हैक्टेयर्स में हो गई सिंचाई क्षमता, उपयोगिता कहां है? उपयोगिता नहीं है तो इसके कारण क्या हैं? अगर कारणों की जांच की गई, अनुशंसाएं लिखी गईं तो भारत सरकार ने क्या कदम उठाए? केवल धनराशि उपलब्ध कराने से ही किसानों को लाभ नहीं मिलता है, क्षमता सृजित होने से किसानों को लाभ नहीं मिलता है, जैसे अभी मिश्र जी कह रहे थे। किसानों को सिंचाई प्राप्त हो, यह किसानों के हित में है, लेकिन केवल धनराशि लगाने से, सिंचाई योजना बना देने से यह काम नहीं चलता है। यह काम करके ही आपके पास अनुशंसायें भेजी जा चुकी हैं, क्या आप यह काम कर सकते हैं

SHRI P. K. THUNGON: Sir, I have mentioned about the steps taken by the Government. Now the hon. Member wants to know the reasons. I would like to state the reasons. The major causes for the lag in utilisation are:

one, over-reporting of the potential;

two, data-base inaccuracy;

three, inadequate development of land and poor water management.

MR. CHAIRMAN: What can we do to utilise it? The Member is conserned about what the Government is doing.

डा० जगन्नाथ मिश्र : अध्यक्ष जी, इन्हीं के मंत्रालय ने समिति बनाई थी, राज्यों के सिंचाई मंत्री उसमें सम्मिलित थे, उन्हीं की अनुशंसायें थी, तो क्या अपने द्वारा गठित समिति की अनुशंसाओं पर इन्होंने ध्यान दिया है?

SHRI P. K. THUNGON: The Committee is formed by the Ministry. They get the fullest attention from us.

SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Sir, I would like to ask of the hon. Minister why, even so many years after Independence, we are not able to provide irrigation facilities to the farmers. We have accepted liberalisation and privatisation in all the fields, especially in the industrial field. It is a fact that the Government is planning to have privatisation in implementation of the irrigation scheme?

SHRI P. K. THUNGON: This is a very important question. In view of the opening up of the economy, we have also proposed that if in irrigation sector also private people come forward with finance for investment, they will be welcome.

SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: I would like to ask on this point also. In Southern Gujarat...

श्री ईश दत्त यादव : सर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आधे घंटे का डिसकसन करादें।

SHRI AJIT P. K. JOGI: Kindly permit a half-an-our discussion on this.

MR. CHAIRMAN: Give a notice for this.

श्री ईश दत्त यादव : सर, मंत्री जी को तो कोई जल्दी नहीं है। इस पर आधे घंटे का डिस्कशन करादें। देश के किसानों के हित के साथ जुड़ा हुआ यह प्रश्न है।

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, in the Statement the hon. Minister has said that out of the initial and on-going projects since the beginning of the Eighth Plan, ten are in Kerala. I know that several projects, which had been started in the Second Plan onwards have not yet been completed. I know of a case where the dam has not yet been completed, but only one canal has been completed. This is the problem. I know in every State the on-going projects are continuing for the last many

years. The cost of the project has gone up because of delays and cost escalations as this work has been continuing for a long time. In this background, I would like to know from the hon. Minister whether he would discuss with the Chief Ministers and the concerned Ministers and impress upon him that the whole money that has been earmarked in the Eighth Plan for this purpose should be utilised on the on-going projects alone in order to complete all these projects. Will he take up this matter?

SHRI P. K. THUNGON: We will certainly like to consult the State Ministers or Chief Ministers, wherever necesary. It has been our approach that in such cases we convene meetings and discuss with them and see in what manner the State Gvernments can be assisted or guided by the Central Government. in this case the Ministry of Water Resource Development.

*187. [*The Questioner (Shrimati Sarla Maheshwari) was absent. For answer vide Col...infra.*]

UNDP Report on HRD

*188. SHRI P. UPENDRA: †
SHRI K. M. KHAN:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a tact that India is 135th out of 173 countries in terms of investment in Human Resource Development according to UNDP Report, 1994;

(b) whether it is a fact that UNDP has suggested that 20 per cent of the national budgets should be earmarked for Human Resource Development; and

(c) what is the percentage and quantum of budgets of the Central and State Governments allocated for education, youth activities and sports giving separate figures?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) According to Human Development Report, 1994 (HDR), India ranks 135th out of 173 countries in terms of the Human Development Index.

(b) HDR had proposed that 20 per cent of national budget of developing countries and 20 per cent of industrial country aid should be allocated to human priority expenditure which includes basic education, universal primary health care, access to sanitation and drinking water and family planning.

(c) During 1994-95, the outlay on education in the Central budget is Rs. 2423.63 crores, which forms 1.6 per cent of the total Central budgetary outlay. Corresponding figures for sports and youth affairs are Rs. 135.11 crores and 0.08 per cent respectively.

As far as States and Union Territories are concerned, in 1992-93, the budgetary outlay for education was Rs. 22283 crores, which accounted for 23.4 per cent of their total budgetary outlay. Regarding sports and youth affairs, the 1992-93 Plan outlay of States and Union Territories was Rs. 81.58 crores, which forms 0.42 per cent of the total Plan outlay.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): Sir, with your permission I would like to say a few words.

This question relates to a report which has appeared and has been reported widely. Though it is not an official UNDP report, yet still we have to take notice of the same. My humble request to you is that since the subject matters which are covered in the report, to which a reference has been made in this question,

† The Question was actually asked on the floor of the House by Shri P. Upendra.